RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 323
दि. 27.03.2026, शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीएम योगी बोले- जरूरत पड़ने पर ही लें पेट्रोल-डीजल, कहीं कमी नहीं; अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ/गोरखपुर (जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत होने पर ही खरीदारी करने की अपील की। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर चल रही चचार्ओं के बीच राज्य सरकार ने गुरुवार को साफ किया कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, रणवीर प्रसाद ने कहा कि सभी जिलों में मांग के अनुसार पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है और कहीं भी संकट जैसी स्थिति नहीं है।

प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों के आधार पर घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी न करें। सरकार के मुताबिक हाल के दिनों में सोशल मीडिया के जरिए कुछ भ्रामक संदेश फैलाए जा रहे हैं, जिनमें ईंधन की कमी की बात कही जा रही है। इन सूचनाओं को गलत बताते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह शरारती तत्वों की हरकत है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

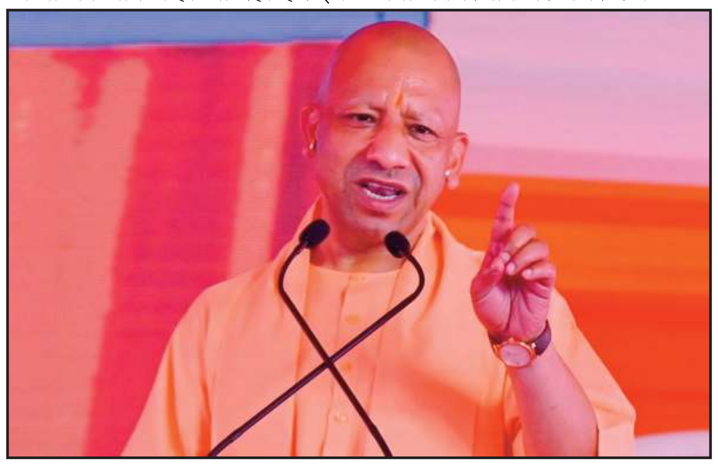

अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की स्थिति पर नजर रखें

प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की स्थिति पर नजर रखें और कहीं भी आपूर्ति बाधित न होने दें। तेल कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाकर अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था भी रखी गई है, ताकि किसी भी स्थिति में आम लोगों को परेशानी न हो।

सरकार ने यह भी कहा है कि अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण करने से आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव पड़ता है। इसलिए आम लोग संयम बरतें और सामान्य जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें। प्रदेश सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

पेट्रोल-डीजल को लेकर किसी भी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। वहीं, लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सदस्य एवं एसआर फिलिंग स्टेशन (इंजीनियरिंग कॉलेज) के मालिक सर्वेश वाजपेई ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पंप 24 घंटे सुचारू रूप से संचालित हैं। लोगों को घबराकर डीजल-पेट्रोल स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग्लोबल मंच पर भारत की दमदार एंट्री, जी 7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी

(एजेंसी)।

पीएम मोदी जून में जी7 समिट के लिए फ्रांस जाएंगे। इससे पहले एस.जयशंकर और जीन नोएल बैरोट की बैठक में पश्चिम एशिया संकट और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा पर चर्चा हुई, जो भारत-फ्रांस संबंधों की मजबूती को दशार्ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून तक होने वाले जी 7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फ्रांस दौरे के दौरान जीन नोएल बैरोट से एबे डे वॉ-डे-सेर्ने में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की भूमिका और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की।

फ्रांस के विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने G7 में भारत के योगदान खासकर वैश्विक आर्थिक असंतुलन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी जैसे मुद्दों को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही यह भी रेखांकित किया गया कि फ्रांस अपनी G7 अध्यक्षता के दौरान भारत को एक प्रमुख साझेदार के रूप में शामिल करने को विशेष महत्व दे रहा है।

बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित और खुला बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। जयशंकर के इस दौरे को भारत-फ्रांस रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

मजबूत होते भारत-फ्रांस के रिश्ते

इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी भारत का दौरा कर चुके हैं, जहां दोनों देशों ने अपने रिश्तों को 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाने पर जोर दिया था।

कुल मिलाकर ऋ7 से पहले भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं।

28 मार्च को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे

प्रधानमंत्री लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के निर्बाध जुड़ाव के साथ बहु-मोडल परिवहन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है

हवाई अड्डे में एक बहु-मोडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे प्रति वर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, इस क्षमता को लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है

हवाई अड्डे की प्रारंभिक यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) होगी, जिसे 70 मिलियन एमपीपीए तक बढ़ाया जा सकता है

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे वे गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में परिकल्पित यह हवाई अड्डा, देश के हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मिलावटी दूध के सेवन से 16 लोगों की हुई मौत का स्वत: संज्ञान लिया है

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उस मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के लालाचेरुवु, चौदेश्वरननगर और स्वरूपनगर क्षेत्रों में फरवरी के मध्य से अब तक मिलावटी दूध के सेवन से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम चार अन्य लोगों का भी इसी तरह के लक्षणों के साथ चिकित्सा उपचार चल रहा है। खबरों के अनुसार दूध में एथिलीन ग्लाइकॉल नामक विषैला पदार्थ मिलाया गया था, जिसके कारण कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। मिलावट का संदिग्ध स्रोत नरसपुरम गांव में स्थित एक डेयरी है, जो क्षेत्र के 100 से अधिक घरों को दूध की आपूर्ति करती है।

पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर, भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर

(जीएनएस)।

पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रमों के मद्देनजर, भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपाय कर रही है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के लिए समर्थन सहित प्रमुख पहलुओं पर अद्यतन जानकारी नीचे दी गई है।

ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद रहने के कारण, भारत सरकार ने देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं। वर्तमान स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

कच्चा तेल/रिफाइनरी

सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक बना हुआ है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है।

रिटेल आउटलेट

देशभर में सभी खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं।

कुछ क्षेत्रों में अफरा-तफरी मचने से खरीदारी की खबरें - कुछ अफवाहों के चलते कुछ राज्यों में खुदरा दुकानों पर अफरा-तफरी मच गई, जिसके परिणामस्वरूप दुकानों पर असामान्य रूप से अधिक बिक्री और भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि, यह सूचित किया जाता है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

सरकार जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दोहराती है। प्राकृतिक गैस

डी-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है।

ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति उनकी औसत खपत के 80 प्रतिशत के बराबर है।

भारत सरकार ने सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने सभी गैस क्षेत्रों में रेस्तरां, होटल और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।

भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित; सरकार ने जानबूझकर चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान की निंदा की

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है। सभी खुदरा ईंधन दुकानों में पर्याप्त आपूर्ति है। कमी नहीं है। जानबूझकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं के सुनियोजित अभियान से गुमराह न हों, इसका उद्देश्य अनावश्यक दहशत फैलाना है। पेट्रोल और डीजलः कोई कमी नहीं, वितरण में कोई रोक नहीं, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधक और पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है, जो 150 से अधिक देशों को परिष्कृत ईंधन की आपूर्ति करता है। विश्व का शुद्ध निर्यातक होने के कारण भारत में घरेलू पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता संरचनात्मक रूप से सुनिश्चित है। देश भर में एक लाख से अधिक खुदरा ईंधन दुकानें खुली हैं।

रेल मंत्री ने कवच कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की

रेलवे की कवच के अंतर्गत विकसित स्वदेशी यूनिवर्सल ब्रेकिंग प्रणाली, कवच 4.0 के त्वरित कार्यान्वयन में सहायक होगी

कवच के अंतर्गत एआई आधारित केंद्रीकृत निगरानी मंच, "सुरक्षा", यातायात निगरानीकताओं को असामान्य घटनाओं के बारे में सचेत करेगा और इस प्रकार उनकी समयबद्ध कार्रवाई से हमारी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में सहायता करेगा

(जीएनएस)।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली कवच की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में तैनाती में तेजी लाने और अधिक कुशल रेलगाड़ी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कवच को आगे बढ़ाने वाली तकनीकी प्रगति

भारतीय रेलवे ने कवच में कई अत्याधुनिक सुधार किए हैं। यूनिवर्सल ब्रेकिंग प्रणाली (यूबीए), जो विभिन्न निमार्ताओं के ब्रेकिंग कर्व्स को मानकीकृत करता है, अंतरसंचालन सुनिश्चित करता है और बार-बार होने वाले परीक्षणों को समाप्त करता है। बेसलाइन सॉफ्टवेयर, एआई-संचालित डिजाइन स्वचालन और लोकोमोटिव, इंटरलॉकिंग प्रणाली और ट्रैक मशीनों के लिए एकीकरण इंटरफेस में महत्वपूर्ण उन्नयन प्रणाली की मजबूती को और बढ़ा रहे हैं।

कवच तैनाती की वास्तविक समय की निगरानी और पूवार्नुमानित रखरखाव को सक्षम करने के लिए एक एकीकृत संचालन प्रबंधन प्रणाली के रूप में एक केंद्रीकृत निगरानी मंच, सुरक्षा, विकसित किया जा रहा है।

अब तक की प्रगति

अब तक कवच को 3,103 किलोमीटर मार्ग पर स्थापित किया जा चुका है। उच्च घनत्व और उच्च उपयोग वाले गलियारों सहित 24,427 किलोमीटर मार्ग पर कवच का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

कवच संस्करण 4.0 के कार्यान्वयन के अंतर्गतः

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे प्रमुख गलियारों पर 1,638 किलोमीटर मार्ग पर पहले ही यह प्रणाली चालू हो चुकी है।

श्री वी. एल. कांता राव ने जल सचिवों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी. एल. कांता राव ने तेलंगाना में राज्य जल सचिवों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की

सम्मेलन में चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और जल क्षेत्र में केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई

(जीएनएस)।

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) के सचिव श्री वी. एल. कांता राव ने तेलंगाना के डॉ. एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान में आयोजित क्षेत्रीय राज्य जल सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर एक साथ उपस्थित हुए। दिन भर चलने वाले सम्मेलन में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के अधिकारियों और विभाग के 15 प्रमुख संगठनों के प्रमुख शामिल हुए।

सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों में शामिल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विभाग की चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा शामिल थी; इन राज्यों में विभाग के संगठनों द्वारा किए गए कार्य, चल रही योजनाओं/परियोजनाओं और अंतर-राज्यीय मामलों के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की चिंताओं को समझना; और केंद्र-राज्य समन्वय और साझेदारी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को और मजबूत करने के लिए इन पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने योजना के कार्यान्वयन की स्थिति, केंद्र सरकार से अपेक्षाओं और जल संसाधन के क्षेत्र में संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित बाधाओं का वर्णन किया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने प्राथमिकता वाले कार्यों की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के लिए चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और केंद्र-राज्य समन्वय में अंतराल को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया।

'समाजवादी पार्टी का ल्यारी राज'; लखनऊ की सड़कों पर लगे अखिलेश के खिलाफ पोस्टर, फिल्म धुरंधर की चर्चा

लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें अखिलेश सरकार के कार्यकाल की घटनाओं का जिक्र किया गया है।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिल्म 'धुरंधर 2' ने अलग ही हंगामा मचाया हुआ है। माफिया डॉन अतीक अहमद की तरह दिखते किरदार की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन से कनेक्शन मामले ने राजनीति गरमाई है। वहीं, अब अखिलेश यादव के शासनकाल को फिल्म में दिखाई गई जगह ल्यारी से तुलना की गई है। करांची के ल्यारी की अपराध और राजनीति के घालमेल को इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म से प्रेरित होकर भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगवाया है। इसमें लिखा गया है, 'सपा का ल्यारी राज, न भूले हैं न भूलेंगे'। अब इस पर राजनीति गरमाती दिख रही है।

क्यों गरमाया है विवाद?

लखनऊ की सड़क पर एक पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस पोस्टर को भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की ओर तैयार कराया गया है। वे कहते हैं कि फिल्म

'धुरंधर' को लेकर लगातार गतिविधियां चल रही हैं।

वे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके शासनकाल की घटनाओं की याद ताजा कराते दिखते हैं। देवेंद्र तिवारी कहते हैं कि राज्य में तब लगातार बलात्कार, हत्याएं और लूटपाट हो रही थी, अतीक अहमद जैसे अपराधी वहां मौजूद थे। अब इस मामले ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है।

देवेंद्र तिवारी ने क्या कहा?

भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने पोस्टर लगाए जाने के मामले में बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लगातार 'धुरंधर' मूवी को लेकर के एक्टिविटी चल रही है(मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को यह देखना चाहिए, जब उनका राज था, प्रदेश को लगातार बलात्कार, हत्याएं, डकैती, लूट जैसी घटनाओं में झोंक रखा था।

फिल्म में दिखाई गई ल्यारी जैसी स्थिति पूरे प्रदेश की हो गई थी।

देवेंद्र तिवारी ने कहा कि जगह-जगह दंगे हो रहे थे। क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही थी। 2012 से 2017 का जो कालखंड था, प्रदेश में कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी, कोई अन्य वर्ग सुरक्षित नहीं थे। बहन-बेटी उस समय असुरक्षित थी। जगह-जगह क्राइम हो रहे थे। लोग मारे जा रहे थे। ल्यारी जैसी स्थिति प्रदेश की बनी हुई थी।

अतीक को मिट्‌टी में मिलाने की बात

देवेंद्र तिवारी ने कहा कि उस काल में अतीक अहमद जैसे अपराधियों को खुली छूट मिली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे मिट्‌टी मं मिलाया है। प्रदेश से क्राइम को खत्म करने में भूमिका निभाई है। प्रदेश की जनता 2012 से 2017 के काल के आतंक राज को भूली नहीं है। इन लोगों ने किस तरह माफियाओं, भूमाफियाओं, जमीनों पर कब्जा करने वालों, बहन-बेटियों के साथ रेप करने एवं जला देने वालों को किस तरह संरक्षण दिया, कोई नहीं भूला है।

भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष ने कहा कि इसी विषय को लेकर मैंने ये पोस्टर्स जगह-जगह लगवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव में सभी लोग जागरूक हैं। लोग जानते हैं कि ल्यारी जैसी स्थिति फिर से उत्पन्न नहीं होने देंगे।

पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह के बाद क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर गुरुवार की सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जुटी रही

(जीएनएस)।
राजधानी लखनऊ /प्रयागराज
प्रयागराज के नैनी में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह के बाद क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर गुरुवार की सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने वालो की लंबी लाइन लगी रही। हालात यह रहा कि पेट्रोल पंपों पर पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ गया। जबकि जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने लोगों से अपील भी किया था कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अफवाहो के चलते लोग बड़ी संख्या में अपने वाहन के ।साथ पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे थे।

– पेट्रोल न मिलने का सता रहा डरा

सभी को इस बात की आशंका थी कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो सकती है। क्षेत्र में लगभग एक दर्जन के करीब पेट्रोल टंकी पर सुबह से ही लोगों की लाइन अपने-अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता से इस बारे में अपील भी किया है कि वह किसी भी ऐसी अफवाह से बचें।

– पेट्रोल खत्म होने पर सप्लाई बंद

नैनी के एक पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म होने के बाद नो इंट्री का बोर्ड लगा दिया गया।बैरिकेडिंग लगाते हुए लोगों को वापस कर दिया गया। पेट्रोल के लिए आने वाले लोगों का कहना था कि बिना पेट्रोल के समस्या हो रही है। यहां टंकी पर पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। हर जगह भीड़ जुटी हुई है। आगे भी। आसार नहीं दिख रहे है कि पेट्रोल मिले

कबाड़ ट्रकों को नई पहचान देकर ऊंचे दामों में बेचने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार

(जीएनएस)।
राजधानी लखनऊ /प्रयागराज
प्रयागराज — यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) फील्ड इकाई प्रयागराज ने अंतरराज्यीय स्तर पर ट्रकों की चोरी, फाइनेंस की गाड़ियों को कबाड़ बनाकर फर्जी कागजात तैयार करने और चेसिस नंबर बदलकर ऊंचे दामों में बेचने वाले एक शातिर गिरोह का पदार्फाश किया है। एसटीएफ ने इस संगठित गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध वाहन और जाली दस्तावेज बरामद किए हैं।

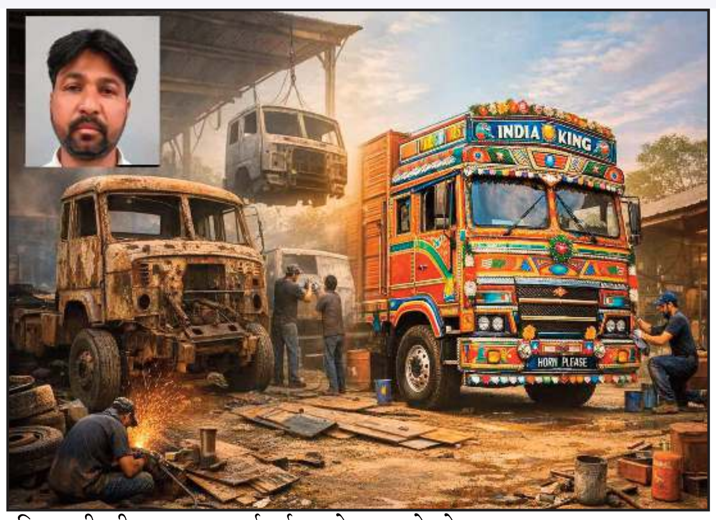

मरियाडीह का रहने वाला है सरगना

मिली जानकारी के अनुसार, एसटीएफ को काफी समय से कबाड़ हो चुके ट्रकों के फर्जी कागजात बनवाकर चोरी या फाइनेंस पर ली गई ट्रकों के चेसिस नंबर और नंबर प्लेट बदलकर बेचने वाले गिरोह की सूचना मिल रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने गिरोह के सरगना कासिम अहमद को गिरफ्तार किया है। कासिम पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मरियाडीह गांव का निवासी बताया जा रहा है।

बरामदगी

एसटीएफ टीम ने सरगना के कब्जे से 16 चक्का वाला एक ट्रक (जिसके कागजात फर्जी थे), महिंद्रा का 6 चक्का वाहन, 12 फर्जी नंबर प्लेट, आधा दर्जन फर्जी रजिस्ट्रेशन कागजात (आरसी) तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

गिरोह के काम करने का तरीका

यह गिरोह विभिन्न प्रांतों से कबाड़ हो चुके ट्रकों को औने पौने दामों में खरीदता था। इसके बाद चोरी किए गए या फाइनेंस पर लिए गए ट्रकों के चेसिस और इंजन नंबर कबाड़ ट्रकों से बदलकर कूटरचित कागजात तैयार करता था। इन वाहनों को प्रयागराज सहित अन्य जिलों में अच्छी स्थिति में बताकर भोले भाले ग्राहकों को ऊंचे दामों में बेचा जाता था।

सरगना को जेल, अन्य की तलाश

एसटीएफ फील्ड इकाई प्रयागराज ने गिरफ्तार सरगना कासिम अहमद के खिलाफ संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। यह कार्रवाई वाहन चोरी और फर्जीवाड़े के खिलाफ एसटीएफ की एक बड़ी और अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

पेट्रोल डीजल के जमाखोरों पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, होगी सख्त कार्रवाई

(जीएनएस)।
राजधानी लखनऊ /प्रयागराज
प्रयागराज। ईरान-इजरायल एवं मध्य पूर्व के संघर्ष के कारण ईंधन की कमी होने संबंधी अफवाहें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैल रही हैं। इसके दृष्टिगत गुरुवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (ना.आ.) विजय शर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह, पेट्रोल/डीजल तथा एलपीजी के समस्त विक्रय अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और पेट्रोल/डीजल व एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महामंत्री उपस्थित रहे।

जिला पूर्ति अधिकारी एवं विक्रय अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार और अफवाहों के कारण ईंधन की अतिरिक्त मांग हो रही है, जिससे पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ बढ़ गई है। जबकि जनपद के 368 पेट्रोल पंपों द्वारा पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आमजन की मांग के सापेक्ष पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण पेट्रोल पंपों में मौजूद है। जनपद के पेट्रोल पंपों पर गुरुवार का प्रारंभिक स्टॉक लगभग 65 लाख लीटर डीजल-पेट्रोल उपलब्ध था, जबकि गत दिवस की डिलीवरी 18 लाख लीटर रही।

इसी प्रकार जनपद के 144 गैस एजेंसियों के माध्यम से सुचारू रूप से एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जनपद में गैस की कोई कमी नहीं है।

जिलाधिकारी ने बैठक में सभी को निर्देश दिया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बिक्री पर लगातार निगरानी रखी जाए। कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से भंडारण या होल्डिंग एवं कालाबाजारी न कर सके। अपर जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी और विक्रय अधिकारी भ्रमण में रहकर कालाबाजारी या होल्डिंग करते पाए जाने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करें। पुलिस से समन्वय स्थापित कर पंप एवं गैस एजेंसी पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।

गैस एवं पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसका मोबाइल नंबर 8299632748, 7388036037, 8126271301, 8853522200, 9956591463, 8299033086 है। जिलाधिकारी ने कंट्रोल रूम से की गई शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं।

दियोरिया कलां गौशाला में गौवंश पर अत्याचार, गौ सेवकों का आरोप गौ सेवकों पर मारपीट व धमकी: क्षेत्राधिकारी को शिकायत

(जीएनएस)।
पीलीभीत। बीसलपुर क्षेत्र के दियोरिया कलां गौशाला में गौवंश के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। गौशाला कर्मचारियों और ग्राम प्रधान के करीबियों ने बुधवार दोपहर लगभग 3:28 बजे गौसेवकों के साथ अभद्रता, गाली-गलौज की। गौसेवक विमलेश वर्मा पुत्र रोशनलाल के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी गई ।शिकायतकताओं ने बताया कि

गौशाला में गोवंश भूख व उचित उपचार न मिलने से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। विमलेश वर्मा, विजय सिंह, आकाश राजपूत, गौरव राजपूत, अंकित बर्मा, राहुल राजपूत, सतीश वर्मा, कौशल श्रीवास्तव, विक्रम सिंह व शिव कुमार पटेल ने क्षेत्राधिकारी बीसलपुर को शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ।प्रार्थीगण ने क्षेत्राधिकारी महोदय को लिखे पत्र में कहा कि आए दिन गौशाला में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने तत्काल जांच व कार्यवाही की मांग की है।

यूपी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बिगड़ेगा मौसम, 5 दिन तक बारिश-ओले और तेज हवा, आईएमडी अलर्ट

यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 26 से 30 मार्च तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश का मौसम

लखनऊः (जीएनएस)। उत्तर भारत में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में आज मौसम बदला-बदला नजर आएगा। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

कुछ इलाकों में आंधी-तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बदलाव के कारण तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

कब और कैसे बदलेगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 26 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की शुरूआत होगी और इसका असर धीरे-धीरे लखनऊ समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगा।

27 मार्चः प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना, कुछ

इलाकों में ओलावृष्टि भी संभव

28 मार्चः मौसम में आंशिक सुधार और थोड़ी राहत

29 मार्चः एक और मजबूत सिस्टम सक्रिय, जिससे फिर से मौसम बिगड़ने की आशंका

30 मार्चः हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है

प्रदेश में दिखेगा मिलाजुला असर

उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण तापमान में कमी आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अब एक बार फिर 26 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी यूपी के करीब 15 जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी।

29 मार्च तक रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान कई स्थानों पर आकाशीय बिजली कड़कने और ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम का असर पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में देखने को मिलेगा।

प्रमुख शहरों का हाल

राजधानी में अधिकतम तापमान 33-37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी संभव है। साथ ही तेज हवाएं चलेंगी।

कानपुर, आगरा, मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में बादल अधिक सक्रिय रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना ज्यादा है। वहीं पूर्वी यूपी में भी छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है।

आंधी-तूफान, बिजली और ओलावृष्टि का खतरा

मौसम विभाग (क्टऊ) के अनुसार, 26 से 29 मार्च के बीच कुछ इलाकों में 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि का खतरा भी बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

किसानों के लिए अलर्ट

इस मौसम परिवर्तन का असर रबी की फसलों पर पड़ सकता है। गेहूं, सरसों और चना जैसी खड़ी फसलों को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान होने की आशंका है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय पहले से कर लें।

सावधानी ही बचाव

बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखें, तेज हवाओं और आंधी के दौरान खुले स्थानों से दूर रहें, पेड़ों और कमजोर ढांचों के पास खड़े न हों

बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

नेशनल हाउसिंग बैंक ने रक्षा, अर्धसैनिक और सरकारी कर्मियों पर केंद्रित 'गृह सुगम पोर्टल' का शुभारंभ किया

'गृह सुगम पोर्टल' एक अभूतपूर्व डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य गृह ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और इसे अधिक किफायती बनाना है

(जीएनएस)।
भारत सरकार द्वारा किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए स्थापित शीर्ष संस्था नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने 'गृह सुगम पोर्टल' का शुभारंभ किया है। यह अभिनव पोर्टल विशेष रूप से रक्षा और सरकारी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है, जिससे वे अपनी वर्तमान पोस्टिंग लोकेशन से ही सरल, तेज तथा सुविधाजनक तरीके से गृह ऋण प्राप्त कर सकें।

यह पोर्टल डिजिटल माध्यम से ऋण लेने को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को गति देगा। यह आवास ऋणों तक बेहतर और आसान पहुंच सुनिश्चित कर आम नागरिकों के लिए घर का सपना साकार करने के अवसरों को विस्तृत करेगा। साथ ही, यह पहल किफायती एवं टिकाऊ आवास वित्त को प्रोत्साहित करते हुए इस दिशा में चल रहे मिशन को और अधिक सशक्त बनाएगी।

पोर्टल की मुख्य विशेषताएंः

ड्ड रक्षा कर्मी, अर्धसैनिक बलों के

सदस्य और अपनी-अपनी प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से डिजिटल रूप से आवास ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋण की स्वीकृति और प्रोसेसिंग के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक एकीकृत डिजिटल मार्केटप्लेस, जो बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सबसे उपयुक्त प्रस्ताव को खोजने में मदद करता है।

एनएचबी और ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ निर्बाध डिजिटल एकीकरण, ताकि परिचालन में सुगमता सुनिश्चित हो सके।

ऋण प्रसंस्करण दक्षता में वृद्धि।

शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण।

जल्दी सवालों के जवाब पाने के लिए ऑनलाइन चैट की सुविधा।

प्रभावः

यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को इसकी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही, रक्षा, अर्धसैनिक और केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी संबंधित प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से सहज रूप से पंजीकरण और आवेदन करने में सक्षम बनाता है। कर्मचारी बहुत ही कम जानकारी प्रदान करके अपने होम लोन का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं, जिसे आगे पंजीकृत ऋणदात्री संस्थाओं को भेज दिया जाता है। इसके बाद, विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ अपने-अपने सर्वोत्तम प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं, जिनकी तुलना कर आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कर सकता है। यह व्यवस्था होम लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाती है—विशेषकर उन रक्षा और अर्धसैनिक बलों के लिए, जो दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। परिणामस्वरूप, यह पहल देश में किफायती आवास के स्वामित्व को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है, 2024-25 में प्रीमियम 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है

निर्धारित समय-सीमा और नियामक उपायों का उद्देश्य स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान में दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना

(जीएनएस)।
भारत का स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र लगभग 9 प्रतिशत की दर से मजबूत वृद्धि दर्ज कर रहा है और 2024-25 में कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की राशि 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। यह वृद्धि बढ़ती जागरूकता, स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण तक बेहतर पहुंच और चिकित्सा खर्चों को लेकर वित्तीय सुरक्षा की बढ़ती मांग को दशार्ती है।

कार्यकुशलता बढ़ाने और पॉलिसीधारकों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है।

नकद भुगतान में लगने वाला समय

आईआरडीएआई द्वारा निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई हैः -

कैशलेस प्री-ऑथराइजेशन - एक घंटे के भीतर।

अंतिम स्वीकृति - तीन घंटे के भीतर।

इन समय-सीमाओं का उद्देश्य देरी को कम करना और यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को समय पर चिकित्सा देखभाल मिल सके।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि :

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि के पीछे पॉलिसीधारकों की बढ़ती उम्र, उच्च कवरेज, उन्नत सुविधाएं आदि जैसे कारक प्रमुख कारण हैं।

आईआरडीएआई के 2024 के नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि बीमा उत्पादों का मूल्य निर्धारण सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों के आधार पर उचित रूप से किया जाए और वे व्यवहार्य और किफायती बने रहें, साथ ही नियुक्त एक्चुअरी द्वारा विश्वसनीय डेटा और ग्राहक प्रतिक्रिया का उपयोग करके आवधिक समीक्षा की जाए।

स्वास्थ्य दावों का निपटान

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए दावों के भुगतान का अनुपात (दावों की संख्या के आधार पर) नीचे दिखाया गया हैः

वित्तीय वर्ष
भुगतान किए गए दावों का अनुपात
(दावों की संख्या के आधार पर)
2022-23
85.66 प्रतिशत
2023-24
82.46 प्रतिशत
2024-25
87.50 प्रतिशत

इसके अलावा, आईआरडीएआई के बीमा भरोसा पोर्टल के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सामान्य और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित 1,37,361 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 1,27,755 (93 प्रतिशत) शिकायतों का निपटारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही कर दिया गया।

दावों की अस्वीकृति या अस्वीकार किए जाने के मामले मुख्यतः पॉलिसी की विशिष्ट शर्तों और सीमाओं के कारण होते हैं। दावों की अस्वीकृति या अस्वीकार किए जाने के कुछ कारणों में बीमित राशि से अधिक राशि, सह-भुगतान खंड, पॉलिसी में उप-सीमाएं, टॉप-अप पॉलिसी में कटौती योग्य राशि, कमरे के किराए पर सीमा, आनुपातिक शुल्क, गैर-चिकित्सा व्यय आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई द्वारा स्पष्टता बढ़ाने, दावों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और पॉलिसीधारकों का विश्वास मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। संक्षेप में, एक पारदर्शी और भरोसेमंद स्वास्थ्य बीमा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों का संतुलित और जानकारीपूर्ण दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

होर्मुज स्ट्रेट जल-डमरू पर यूएस को गोलमोल जवाब देकर साथी देशों का किनारा

राहत की खबर, ईंरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि उसके देश ने भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी गईं है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने शत्रु देशों के जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति बिल्वुल नहीं देगा। दरअसल दुनिया का 20 प्रातिशत नौ परिवहन तेल और गैस सिलेंडर लेकर इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। अब ईंरान ने इसी रास्ते को हथियार बना लिया है और ऊर्जा संकट की शुरूआत हो गईं। अब ईंरानजलड मरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से मोटी फीस वसूल रहा है। यह सच है कि जहां ईंरान ने यह तय कर लिया है कि वह अमेरिका के साथ अब कोईं भी समझौता नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि तेहरान तब तक लड़ेगा जब तक उसके पास लड़ने की ताकत है। इस बात को और स्पष्ट करें तो तात्पर्यं यह है कि ईंरान को इस बात की कोईं परवाह नहीं है कि उसका भविष्य क्या है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने मित्र देशों को जो उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उन्हें टैरिफ मुद्दे को लेकर इतना नाराज कर दिया है कि उसके अनुरोध को कोईं मान ही नहीं रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, जर्मनी, इटली जैसे अपने परम्परागत सहयोगी देशों से कहा कि वे ईंरान के खिलाफ अपने जहाज भेजें किन्तु किसी भी देश ने उसकी बात मानी ही नहीं, सभी ने गोलमोल जवाब देकर किनारा कर लिया। ये वे देश हैं जो अमेरिका के इशारे पर अपनी वूटनीति और रणनीति बनाते थे। बात यहीं तक नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि कभी अमेरिका की एक आवाज पर उसके लिए मरने और मारने के लिए तैयार रहने वाले देश अब ईंरान को संकेत दे रहे हैं कि उनकी उससे कोईं दुश्मनी नहीं है। यह सच है कि आज ईंरान के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है, खतरा मौजूदा नेतृत्व के अस्तित्व के सामने है लेकिन इजरायल के लिए ईंरान के परमाणु कार्यंव्रम जरूर चुनौती बनकर खड़े हैं। इजरायल में कोईं भी सरकार हो वह ईंरान के परमाणु कार्यंव्रमों पर हमले की कोशिश जरूर करेगा। इसलिए जब तक ईंरान और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने वाली कोईं सरकार ईंरान में नहीं आती तब तक इसी तरह बवाल होता रहेगा। असल में इजरायल 2021-22 में खाड़ी के देशों से अपने संबंध तेजी से एक बार फिर सुधार रहा था। यूएईं और सऊदी अरब से उसके व्यापारिक व वूटनीतिक रिश्ते तेजी से सुधर रहे थे। किन्तु यह देखकर ईंरान को लगा कि इससे तो इजरायल स्वीकार्यंता इस्लामिक देशों में बढ़ जाएगी। सुप्रीम लीडर ने हमास से 7 अक्टूबर को निदरेष इजरायली नागरिकों पर हमला करवा दिया। इसके बाद इजरायल ने हमास को नेस्तनाबूद करने का संकल्प ले लिया। किन्तु ईंरान ने इसके बाद अपने परमाणु हमले का डर दिखाकर फिर सीधे इजरायल को चुनौती दी। यहीं से ईंरान निशाने पर आ गया और इजरायल ने अमेरिका को ईंरान के साथ युद्ध में पूरी तरह शामिल कर लिया। अब अमेरिका और इजरायल को सोचना है कि वे युद्ध कहां तक आगे बढ़ा सकते हैं जबकि ईंरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के नेतृत्व में चल रही तेहरान की सत्ता को यह तय करना है कि उन्हें अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने से क्या मिलने वाला है। इस वक्त ईंरान में कोईं सुप्रीम लीडर नहीं है इसलिए रिवोल्यूशनरी गार्ड पैसले भी ले रहा है और उसे लागू भी कर रहा है। इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि अयातुल्लाह खामेनेईं के जिस बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया था उस पर भी हमला हुआ है और वह कोमा में है, जब कि उसके बेटे को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले ही मार दिया है। यही कारण है कि ईंरान में सत्ता परिवर्तन की पूरी संभावना है लेकिन ईंरान चाहता है कि वह सब वुछ इतनी आसानी से अमेरिका की चाहत को पूरा नहीं होने देगा। बहरहाल ईंरान पांच देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति देकर इतना संकेत तो दे ही दिया कि जो देश उसके खिलाफ खड़े नहीं हैं, उन्हें वह परेशान नहीं करना चाहता। यही भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है।

आम चुनाव और उपचुनाव 2026: 400 करोड़ रुपये से अधिक जब्ती

(जीएनएस)।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव के लिए 15 मार्च, 2026 को होने वाले चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया है। आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की थी, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई, समन्वय को बढ़ाया गया और उन्हें 24 मार्च, 2026 को हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

इसे सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं ताकि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जा सके। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर अचानक नाकेबंदी करने के लिए 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं ।

26 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के सक्रिय होने के बाद से, 25 मार्च, 2026 तक, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कई प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से 408.82 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त की गई हैं, जिनमें 17.44 करोड़ रुपये नकद, 37.68 करोड़ रुपये (16.3 लाख लीटर) की शराब, 167.38 करोड़ रुपये की ड्रग्स, 23 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं और 163.30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य मुफ्त वितरण वाली वस्तुएं शामिल हैं।

आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्देशों के प्रवर्तन के लिए की जाने वाली जांच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिए जिला शिकायत समितियां भी गठित की गई हैं।

नागरिक/राजनीतिक दल सी-विजिल मॉड्यूल का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं।

ईसीआईएनईटी.

15 मार्च से 25 मार्च तक, आम चुनाव और उपचुनाव वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सी-विजिल ऐप के माध्यम से 70,944 शिकायतें दर्ज की गई हैं । इनमें से 70,831 शिकायतों का निपटारा हो चुका है और 67,899 शिकायतें, यानी 95.8 प्रतिशत शिकायतें, 100 मिनट के भीतर हल हो गईं।

शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें कॉल सेंटर नंबर 1950 भी शामिल है, जिसके माध्यम से जनता का कोई भी सदस्य या राजनीतिक दल संबंधित डीईओ/आरओ के पास शिकायत दर्ज करा सकता है।

श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का अध्ययन करने के लिए डीडीडब्ल्यूएस का दौरा किया

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जेजेएम और एसबीएम-जी डिवीजनों द्वारा प्रस्तुत ज्ञानवर्धक प्रस्तुति साझा की

(जीएनएस)।

श्रीलंका की संसद की इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक विकास संबंधी क्षेत्रीय निगरानी समिति का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में एक सप्ताह के आधिकारिक अध्ययन दौरे पर भारत में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सांसद (अध्यक्ष) श्री एस.एम. मारिक्कर कर रहे हैं।

इस यात्रा के अंतर्गत, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने यात्रा को सुगम बनाया और आज दोपहर गणमान्य व्यक्तियों के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) पर एक विस्तृत प्रस्तुति का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम के दौरान डीडीडब्ल्यूएस के सचिव श्री अशोक के.के. मीना, एनजेजेएम के अपर सचिव और मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोआन और डीडीडब्ल्यूएस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए, ग्रामीण एवं ग्रामीण जल संसाधन विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के सचिव श्री अशोक के.के. मीना ने भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत पर प्रकाश डाला कि केंद्र और राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के लाभ के लिए बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करती हैं, ताकि वे जमीनी स्तर पर लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान कर सकें। उन्होंने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को अवगत कराया कि भारत ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता से संबंधित दो प्रमुख मिशनों: वर्ष 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन (जेजेएम) और वर्ष 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) को लागू कर रहा है।

उन्होंने इन दोनों मिशनों के कार्यान्वयन से भारत को प्राप्त प्रमुख सीखों को चार मुख्य बिंदुओं में साझा किया :

ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकरण और समुदाय-नेतृत्व वाली सेवा वितरण प्रणाली, जिससे समुदाय जल और स्वच्छता सेवाओं का स्वामी और प्रबंधक बन सके।

सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय।

मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता, तत्क्षण निगरानी और शिकायत निवारण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।

योजना के डिजाइन में स्थिरता, जिसमें दूषित जल का प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के सिद्धांत शामिल हैं।

सत्र को आगे बढ़ाते हुए, जेजेएम और एसबीएम-जी के अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जेजेएम के निदेशक श्री हरि नारायणन मुरुगन ने पेयजल क्षेत्र में भारत-श्रीलंका सहयोग पर एक व्यापक प्रस्तुति दी। उन्होंने भारत में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की यात्रा की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश के प्रत्येक ग्रामीण घर को उनके दरवाजे पर पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऐतिहासिक घोषणा के परिणामस्वरूप जल जीवन मिशन का शुभारंभ हुआ, जिसमें सभी ग्रामीण घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने की प्रतिबद्धता शामिल है।

पेयजल की व्यापक पहुंच के लिए इस मिशन को पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है, जिनमें मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त सार्वजनिक वित्तपोषण, साझेदारी, जन भागीदारी और ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि मिशन की शुरूआत लगभग 55 अरब डॉलर के बजट से हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर लगभग 92 अरब डॉलर कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी की उपलब्धता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जो 17 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई है और अब 15 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध है।

अपनी बातों को जारी रखते हुए श्री हरि ने बताया कि मिशन का विस्तारित चरण एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च, 2026 को मंजूरी दी थी। मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाकर जेजेएम 2.0 के रूप में विस्तारित किया गया है और इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है। सरकार संरचनात्मक सुधारों, निरंतर जन भागीदारी, परिचालन और वित्तीय स्थिरता, नागरिक-केंद्रित जल गुणवत्ता प्रबंधन और सुजलम भारत राष्ट्रीय परिसंपत्ति रजिस्ट्री के माध्यम से डिजिटल डेटा प्रबंधन पर विशेष बल दे रही है। मिशन का उद्देश्य हर स्तर पर स्पष्ट भूमिका निर्धारण, ग्राम पंचायतों और जिला तकनीकी इकाइयों को सशक्त बनाकर और एक पेशेवर उपयोगिता दृष्टिकोण अपनाकर यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण जल आपूर्ति योजना अगले 30 वर्षों तक पूरी तरह से कार्यरत रहे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जेजेएम 2.0 इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित दृष्टिकोण से हटकर संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है, जो जन भागीदारी पर केंद्रित है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम), राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएसएम) और जल अर्पण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि न केवल प्रत्येक ग्रामीण घर को सुनिश्चित नल का पानी उपलब्ध कराया जाए, बल्कि देश में एक पारदर्शी और दीर्घकालिक ग्रामीण जल के इकोसिस्टम के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध कराया जाए।

एसबीएम-जी की उप सचिव श्रीमती कृतिका कुलहारी ने श्रीलंका के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के समक्ष स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीणः भारत की ग्रामीण स्वच्छता यात्रा - ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) विषय पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रस्तुति में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की यात्रा अक्टूबर 2014 में शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना था। 2 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस मिशन को और गति मिली, जब देश भर के सभी जिलों और गांवों ने स्वयं को ओडीएफ घोषित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) ने प्रथम चरण में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति प्राप्त करने से लेकर द्वितीय चरण में ओडीएफ परिणामों को बनाए रखने और व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन तक का सफर तय किया है, जिसमें गांवों को ओडीएफ प्लस और "आदर्श गांव" बनाने पर जोर दिया गया है।

जन आंदोलन के व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से, वर्ष 2019 तक शत-प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया, जिसमें 12 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6.2 को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने एसबीएम-जी चरण-2 के प्रमुख घटकों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं:

शेष और नए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएलएस) का निर्माण

सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी), विशेष रूप से प्रवासी आबादी और भूमिहीन परिवारों के लिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जैव अपघटनीय, गैर-जैव अपघटनीय और प्लास्टिक अपशिष्ट)

तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ग्रेवाटर और मल कीचड़)

सतत व्यवहार परिवर्तन के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) और क्षमता निर्माण

उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए 12 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों, दिव्यांगजनों, भूमिहीन मजदूरों, लघु एवं सीमांत किसानों और महिला प्रधान परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। मिशन के शुभारंभ के बाद से अब तक 12 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, देश भर में 2.72 लाख से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं।

दो प्रस्तुतियों के बाद, एक खुला और संवादात्मक चर्चा सत्र आयोजित किया गया, जिसके दौरान श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने सतत ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अवसंरचना के लिए भारत के सफल दृष्टिकोणों पर सक्रिय रूप से विचारों का आदान-प्रदान किया।

मंच को संबोधित करने के क्रम में, श्रीलंकाई प्रतिनिधियों ने प्रमुख चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जल निकायों में पारे से संबंधित प्रदूषकों सहित भारी धातुओं का उच्च स्तर बना हुआ है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। उन्होंने जल उपचार के आर्थिक बोझ के बारे में बताया कि श्रीलंका में उपचारित पेयजल का उपयोग न केवल पीने के लिए बल्कि धुलाई, सफाई और अन्य घरेलू कार्यों के लिए भी किया जाता है। इस बहुउद्देशीय उपयोग से लागत में काफी वृद्धि होती है, क्योंकि शुद्धिकरण में किए गए भारी निवेश का उपयोग पीने योग्य मानकों से परे अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, जिससे लागत कम हो जाती है। इन प्रमुख मुद्दों के आधार पर, प्रतिनिधियों ने भारी धातुओं को हटाने के लिए सहयोगात्मक नवाचारों और किफायती प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया और डीडीडब्ल्यूएस भागीदारों से किफायती और व्यापक जल प्रबंधन समाधान साझा करने का आ'ान किया।

सत्र के समापन के बाद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की संयुक्त सचिव (जल) श्रीमती स्वाति मीना नाइक ने अपने समापन भाषण में पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आपसी समझ, ज्ञान साझाकरण और निरंतर द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से भारत और श्रीलंका जल प्रबंधन एवं स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए एक मजबूत साझेदारी स्थापित कर सकते हैं।

जन्नतुल बकी के विध्वंस के विरोध में आज शहीद स्मारक पर जुटेगा शिया समुदाय

लखनऊ। सऊदी सरकार द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व मदीना स्थित पवित्र 'जन्नतुल बकी' के कब्रिस्तान में पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद की सुपुत्री हजरत फात्मा (स.अ.) और उनके परिवार की पवित्र कब्रों को ध्वस्त किए जाने के विरोध में आज राजधानी में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।

ऑल इण्डिया शिया हुसैनी फण्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमे संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद जकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें इस क्रूर फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्था इस वर्ष भी होने वाले विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन करती है।

ALL INDIA SHIA HUSAINI FUND LUCKNOW
ऑल इण्डिया शिया हुसैनी फॅण्ड, लखनऊ

प्रदर्शन का विवरणः

नेतृत्व मौलाना यासूब अब्बास

स्थान शहीद स्मारक, लखनऊ

समय दोपहर 12:30 बजे

प्रतिभागः संस्था के महासचिव हसन मेंहदी (झब्बू) के नेतृत्व में सभी सदस्य और पदाधिकारी प्रदर्शन में शामिल होंगे।

विशेष व्यवस्थाः भीषण गर्मी को देखते हुए शिया हुसैनी फण्ड द्वारा प्रदर्शनकारियों और आम जन के लिए मोबाइल पानी की सबील (चलती-फिरती प्याऊ) का विशेष प्रबंध किया गया है।

संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि हर वर्ष ईद माह (शव्वाल) की 8 तारीख को पूरा विश्व इस काले दिवस को मनाता है और हमारी मांग है कि पवित्र मजारों का पुनः निर्माण कराया जाए।

कलर्स का डॉ. आरंभि व मन्नत हर खुशी पाने की महासंगमः एक सशक्त महिला गठबंधन का प्रदर्शन

दोनों सबसे पसंदीदा फैमिली ड्रामा अब एक साथ लौट रहे हैं! डॉ.

आरंभि और 'मन्नत हर खुशी पाने की' कलर्स पर एक धमाकेदार महासंगम लेकर आ रहे हैं, जिसमें भरपूर होगा स्पेक्टेकल, इमोशन और जबरदस्त टकराव। इस खास क्रॉसओवर में दिखेगा कि जब एक महिला दूसरी महिला का साथ देती है, तो कहानी में कैसे बड़ा मोड़ आता है। इस एपिसोड में आरंभि (ऐश्वर्या खरे) अपनी दुनिया से आगे बढ़कर मानत (आयेशा सिंह) की उथल-पुथल भरी जिंदगी में कदम रखती हैं जहां महत्वाकांक्षा की कीमत चुकानी पड़ती है, ताकत कई रूपों में छिपी होती है और जीने के लिए हिम्मत चाहिए। सहजता और सहानुभूति से जुड़ी ये दोनों महिलाएं सिर्फ जवाबों के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वासों के लिए लड़ती हैं।

सलूजा मैन्शन में विक्रांत (अदनान खान) और याशिका (लीना जुमानी) का भव्य संगीत समारोह शुरू होता है। जो रात संगीत और जश्न से सजी थी, वह जल्द ही भावनाओं के प्रेशर कुकर में बदल जाती है। मानत एक ही मकसद लेकर आती है अर्जू. की असली पहचान उजागर करना। वह साहसिक कदम उठाते हुए उसका ड्रिंक स्पाइक करती है, जो या तो उसका राज खोल देगा या पूरी तरह उल्टा पड़ सकता है। जैसे-जैसे गुस्सा बढ़ता है और रिश्तों की वफादारी टूटने लगती है, आरंभि सामने आती है और मानत का मजबूती से साथ देती है। वह हर कदम पर मानत को सपोर्ट करती है और सच को सामने लाने में मदद करती है। आरंभि के साथ होने से दांव और ऊंचे हो जाते हैं और टकराव और भी तीव्र। लेकिन जब हालात चरम पर पहुंचते हैं, क्या अर्जू. को आखिरकार अपनी असली पहचान बतानी पड़ेगी?

आयेशा सिंह, जो मन्नत हर खुशी पाने की में मानत का किरदार निभा रही हैं, कहती हैं, 'मानत की यात्रा हमेशा से दृढ़ता की रही है ऐसे सपने देखने की, जिन्हें समाज बार-बार सीमित करने की कोशिश करता है। वह लड़ाइयों से अनजान नहीं है; बल्कि उसने कई लड़ाइयाँ अकेले लड़ी हैं, अपनी ताकत और विश्वास पर भरोसा करके। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। उसके साथ आरंभि है—एक उद्धारकर्ता नहीं, बल्कि एक मजबूत साथी, जो मुश्किल वक्त में उसकी ताकत बढ़ाती है। महिलाएं अक्सर एक जैसी सामाजिक दबावों और जीवन के मोड़ों से गुजरती हैं, और यही इस रिश्ते को इतना नैचुरल बनाता है। यह लेन-देन नहीं है, बल्कि साझा अनुभव और सच्चे सपोर्ट से आता है। किसी दूसरी महिला द्वारा समझे जाने और सपोर्ट किए जाने में एक अद्भुत ताकत है। उम्मीद है कि यह महासंगम उन सभी महिलाओं से जुड़ पाएगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक-दूसरे को संभालती हैं।'

ऐश्वर्या खरे, जो डॉ. आरंभि में आरंभि का किरदार निभा रही हैं, कहती हैं, 'आरंभि अब एक नए दौर में कदम रख रही है, जहां उसका मकसद और महत्वाकांक्षा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस पल में उसकी ताकत का अलग रूप दिखता है। जब वह मानत से मिलती है, तो उसे वही मोड़ याद आता है जहां वह खुद खड़ी थी—सवालों में घिरी, कोने में धकेली गई, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। उनका रिश्ता सहानुभूति से जन्म लेता है। आरंभि मानती है कि जब महिलाएं एक-दूसरे की

लड़ाइयों को पहचानती हैं, तो वे हीलिंग पैदा करती हैं। यह बेहद ताकतवर संदेश है, जो बताता है कि सामूहिक कार्रवाई से हम असली दुनिया में भी उन चीजों को बदल सकते हैं, जिन्होंने हमें पीछे खींचा है।'

'मन्नत' ७ 'डॉ. आरंभि' का महासंगम एपिसोड देखें शाम 7:30 बजे, सिर्फ कलर्स पर।

पारिवारिक विवाद में पति ने की लोहे की प्रेस से पत्नी की हत्या

(जीएनएस)।

राजधानी लखनऊ /प्रयागराज

प्रयागराज = झूंसी के चमनगंज इलाके में पारिवारिक विवाद में एक महिला की उसके पति ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद के दौरान पति ने लोहे का प्रेस पत्नी के सिर पर मार दिया। इससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को सुबह हुई। आरोपी पति पुलिस हिरासत में है। दंपती की शादी वर्ष 2021 में मेट्रोमोनियल साइट के माध्यम से हुई थी। अमृतसर पंजाब का मूल निवासी हेमंत काफी समय से झूंसी के चमनगंज इलाके में रहता है।

वह बैग सिलाई और रिपेयरिंग का कार्य करता है। उसकी शादी स्वीटा (40) नाम की महिला से वर्ष 2021 में मेट्रोमोनियल साइट के माध्यम से हुई थी। दोनों को एक बच्ची है। पुलिस के अनुसार विवाह के बाद से ही दंपती के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था।

बुधवार की रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई जो मारपीट में बदल गई। इसी दौरान हेमंत ने घर में रखे लोहे के वजनी प्रेस से स्वीटा के सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। उसकी रात में ही मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को सुबह दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। घर में हेमंत की मां और बहन भी रहती हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

लाखों का सचिवालय पड़ा वीरान महिलाओं ने बना दिया उपले पाथने का स्थान

14 किलोमीटर दूर ब्लॉक जाने को मजबूर ग्रामीण, गांव में सुविधाएं ठप

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर, । ब्लॉक बिलसंडा क्षेत्र के गांव पिपरिया संजरपुर में लाखों रुपये की लागत से बना पंचायत सचिवालय ग्रामीणों के लिए बेकार साबित हो रहा है। सरकार की मंशा थी कि इस भवन के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आसानी से मिल सके, लेकिन स्थानीय स्तर पर लापरवाही के चलते यह उद्देश्य अधूरा रह गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सचिवालय अधिकांश समय बंद रहता है। पंचायत सहायक भी कभी समय पर उपस्थित नहीं होते, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालत यह है कि गांव की महिलाएं सचिवालय के मुख्य गेट के सामने उपले पाथ रही हैं, जिससे वहां

गंदगी का अंबार लग गया है। इस वजह से ग्रामीण सचिवालय के पास जाने से भी कतराने लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सचिवालय के बंद रहने के कारण उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए करीब 14किलोमीटर दूर ब्लॉक कार्यालय जाना पड़ता है। इससे समय और पैसे दोनों की बबार्दी हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि सचिवालय नियमित रूप से खुले तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है। गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान मंजू देवी और ग्राम विकास अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पांच साल के कार्यकाल में कोई ठोस विकास कार्य नहीं कराया गया। कई निर्माण कार्य आज भी अधूरे पड़े हैं और गांव की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकी हैं। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल सका। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सचिवालय को नियमित रूप से खुलवाया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि गांववासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

रामशरणदास भगवतदास हनुमान मंदिर में मां भगवती का भव्य जागरण का आयोजन

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी । मसौली स्थित रामशरणदास भगवतदास हनुमान मंदिर मसौली मे बीती रात्रि मां भगवती का भव्य जागरण का आयोजन किया गया। जिसमें माता के गुणगान के साथ झांकियां भी प्रस्तुत की गई ।रात भर चले जागरण में सभी श्रद्धालु माता के गुणगान सुन झुमते रहे । कार्यक्रम की शुरूआत माता रानी की ज्योति प्रज्वालित कर की गई।

जे एम डी जागरण म्यूजिकल गुप बाराबंकी के गायकों मां दुर्गा के एक से बढ़कर एक भजन गाकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया । सर्वप्रथम माता रानी का पूजन यजमान मोहिंत हिंदु व उनकी पत्नी सोनिका को पुजारी बाबा रामलाल दास व अभय प्रताप मिश्रा ने विधि विधान से पूजा कराते हुए माँ की ज्योति प्रजवल्लित कराई तथा माँ का आवाहन व गणेश वंदना आकाश साई लखनऊ ने मेरी आन रखना माँ मेरी शान रखना इसके तत्पाश्चत गणेश वंदना

गणपति लाखों मेरी लाज ।

पूरन की जो मेरे काज ।।

सीतापुर की गायिका सोनी शर्मा ने प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बाटूँगी, जय श्री राधे जय श्री राधे, बाराबंकी से आये गायक शिव मास्टर ने गया कि जल गये सारे रिस्तेदार जब से माँ तेरी कृपा हो गयी, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है।

कानपुर से पधारे शौरभ अलबेला व कलाकारों द्वारा गणेश शिवशंकर भोलेनाथ माता पार्वती राधे कृष्ण द्वारा बृज की होली, सुदामा चरित्र , राम दरबार व बाहुबली हनुमान जी की , काली माता आदि की झांकियां प्रस्तुत की गई ।जागरण के बाद ताराानी की फिर मन्दिर के पुजारी रामलाल दास ने माता रानी की आरती की हलुआ चना का प्रसाद वितरण किया गया।

इस मौके पर भाजपा नेता डा0 विवेक कुमार वर्मा, आयोजक राहुल ठाकुर, सोनू जैन, मनोज यादव, पंकज नाग, कैलाश नाग, लवकुश यादव, रिषभ गुप्ता, ओमनाग अनिल सैनी, घनश्याम वाल्मीकि, प्रेमनंद वर्मा, देवी शंकर , डा0 शत्रोहन लाल विश्वकर्मा आदि भक्त गण मौजूद रहे।

कच्छियनपुरवा में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम ने जांच के दिए निर्देश

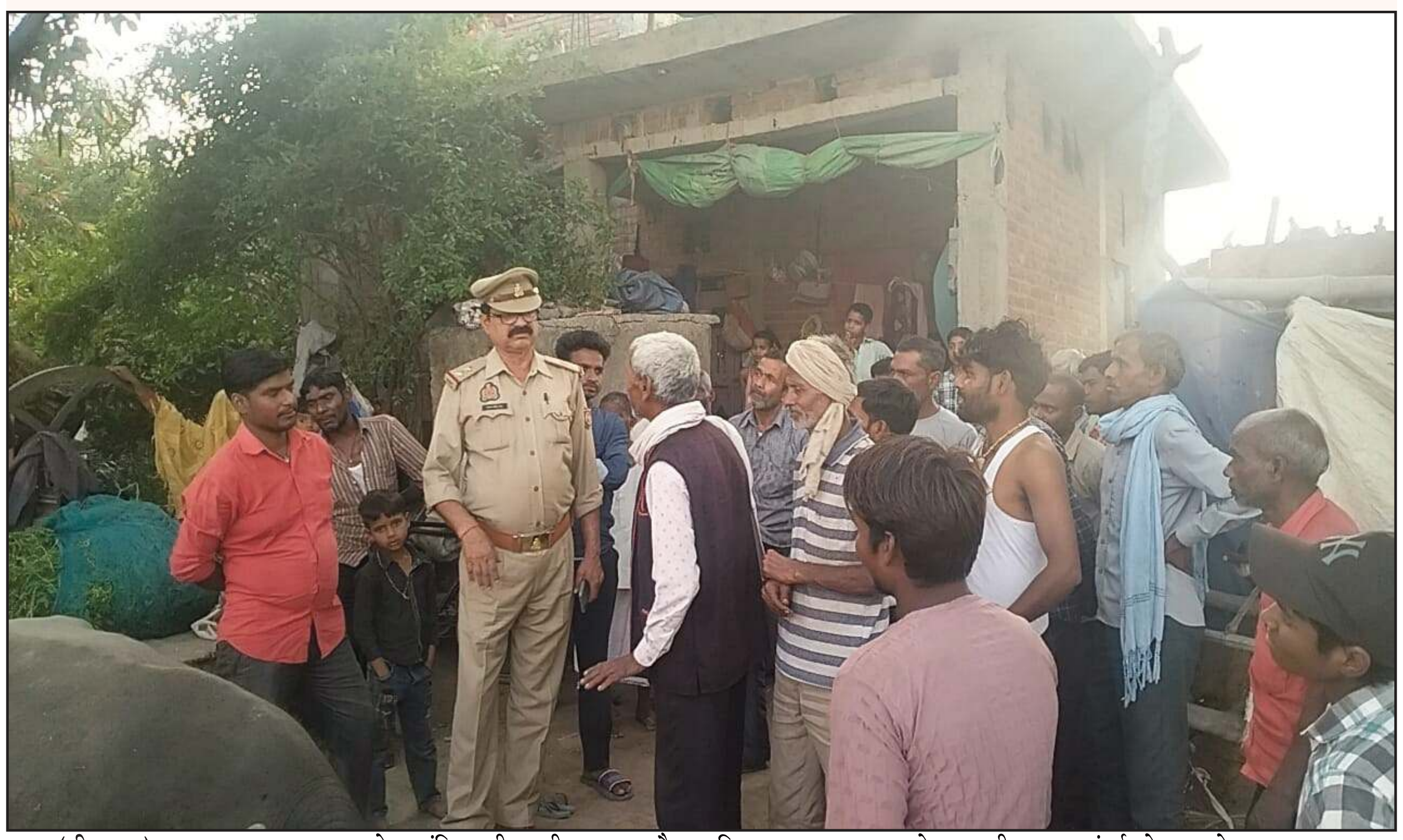

(जीएनएस)। उन्नाव

बांगरमऊ थाना क्षेत्र के कच्छियनपुरवा गांव स्थित प्राचीन मंदिर पूजनीय कुआं की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मंदिर की भूमि को सुरक्षित करने और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे कई बार प्रशासन और पुलिस से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

कच्छियनपुरवा गांव निवासी मेधाई, राजाराम, अमरसिंह, इंदल, मंगली, रामनाथ, तुलसी, रामदीन, मंगतराम, मैकू, छत्रपाल, अनीस, दिनेश, सुरेश, अवधेश, राजबहादुर, विजयपाल, रूपन, स्वदेश, खुशीराम ग्राम प्रधान समेत सैकड़ों लोगों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन देकर पूजनीय जमीन को मुक्त कराए जाने की मांग की है।इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी एकता का परिचय दिखाते हुए जमकर नारेबाजी भी की.जान चली जाए पूजनीय स्थान पर कब्जा नहीं होने देंगे.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के तीन पूजनीय स्थान मंदिर, कुआं और होलिका की जमीन पर अपनी दबंगई के चलते कब्जा कर रखा है।जब पूरा गांव एक तरफ होकर कब्जा छोड़ने की बात कही तो दबंग लोग दबंगई दिखाते हुए धमकाने लगे.हालांकि ग्रामीण सीएम पोर्टल, डीएम साहब और एसडीएम साहब से कब्जा हटवाए जाने की मांग की है।

एसडीएम बृजेंद्र मोहन शुक्ला ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के आदेश दिए हैं।

गौशाला में 2 दिन में 8 गौवंशों की मौत: चारा आपूर्ति संस्था का ठेका निरस्त, एसडीएम ने दिए आदेश

(जीएनएस)।

पीलीभीत के बरखेड़ा स्थित मूसेपुर जयसिंह गौशाला में पिछले 48 घंटों के दौरान 8 गौवंशों की मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने गुरुवार को गौशाला परिसर में प्रदर्शन किया और चारा आपूर्ति करने वाली संस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया।

ग्रामीणों और प्रधान प्रतिनिधि दिगंबर दयाल ने आरोप लगाया कि गौशाला में गौवंशों को गुणवत्ताहीन चारादिया जा रहा था। उनके अनुसार, गेहूं के भूसे के बजाय चारे में सरसों के डंठल (तुरी) मिलाकर खिलाया जा रहा था। इस पोषकहीन चारे के कारण पशु बीमार पड़ रहे थे।

गौवंशों की मौत की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण गौशाला पहुंचे और प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खंड विकास अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरपाल सिंह मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान गौशाला में अव्यवस्थाएं और कई बीमार पशु पाए गए। इसके बाद उपजिलाधिकारी नागेंद्र पांडेय ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।

एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने पशु चिकित्साधिकारी को बीमार गायों के तत्काल उपचार और मृत गौवंशों के शवों के उचित निस्तारण के निर्देश दिए। लापरवाही सामने आने के बाद एसडीएम ने खंड विकास अधिकारी को चारा आपूर्ति करने वाली संस्था का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया।

एसडीएम नागेंद्र पांडेय ने बताया, "मामले की जांच के लिए मैं स्वयं मौके पर गया था। वहां कुछ गायें बीमार मिली हैं और गौवंशों की मृत्यु की पुष्टि हुई है।

लापरवाही अक्षम्य है। पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है और दोषी संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।"

विकासखंड बिलसंडा के ग्राम बेहटा में प्रधान अम्बरिश मिश्रा बा सचिव प्रियांशु द्विवेदी के द्वारा ग्राम निधि में जमकर डाला गया डाका

(जीएनएस)।

बिलसंडा विकास खण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेहटा में विकास कार्यों के नाम पर बडे बडे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए है। ग्राम प्रधान अम्बरीश मिश्रा और पंचायत साचव प्रियांशु द्विवेदी पर आरोप है कि उन्होंने अमृत सरोवर के जीर्णोद्धार के नाम पर लाखों रुपये की सरकारी धनराशि का बंदरबांट कर दिया,ग्रामीणों का आरोप है कि अमृत सरोवर के सौंदर्य करण और जीर्णोद्धार के लिए आई सरकारी धनराशि को नियमों के विपरीत खर्च दिखाकर खुलेआम पीली इंटों का खडंजा बिछा दिया गया, जो न केवल मानकों के विपरीत है बल्कि कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है,ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान और सचिव ने मिलकर इस पूरे कार्य में भारी अनियमितताएं की है और प्रशासन को चुनौती देते हुए घटिया निर्माण कराया गया है। मामले में विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी अमित शुक्ला की संलिप्तता और उदासीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि शिकायतों' के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई जिससे भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण मिलने की चर्चा क्षेत्र में जोरों से हो रही है,ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियो के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तो अमृत सरोवर के नाम पर हुए लाखों रुपये के घोटाले की परतें खुल सकती हैं इस मामले को लेकर जब सचिव प्रियांश द्विवेदी को फोन से संपर्क किया गया तब उन्होंने फीन नहीं उठाया और उसके बाद विकासखंड अधिकारी अमित शुक्ला जी से बात की गई तब उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र मिलने के बाद कार्यवाही की जाएगी अभी 'तक कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर भ्रष्टाचार के मामले को किस स्तर पर संज्ञान में लेकर जांच शुरू करता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस प्रकरण ने विकास कार्यों की पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।

बीसलपुर बिजली घर में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता परेशान, छोटे बकाया पर लाइट कट, बड़े बिल पर चुप्पी

(जीएनएस)।

बीसलपुर बिजली घर में लगे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बन गए हैं। जिन घरों में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हैं, वहां महज 100 रुपये का बकाया होने पर भी मीटर पूरी बिजली आपूर्ति काट देता है। दूसरी ओर, कुछ उपभोक्ताओं के 10 से 12,000 रुपये तक के बकाया होने पर भी उनकी लाइटें बिल्कुल सामान्य चल रही हैं,इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से नाराज उपभोक्ता बिजली विभाग के कार्यालयों के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होकर शिकायत दर्ज कराने को मजबूर हैं। कई घंटों की प्रतीक्षा के

बावजूद उनकी परेशानी का समाधान नहीं हो पा रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर की यह अनियमित कार्यप्रणाली गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, जबकि बड़े बकायेदार बच निकल रहे हैं,बिजली विभाग ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट सफाई नहीं दी है। उपभोक्ता आशा कर रहे हैं कि जल्द ही इस सिस्टम में सुधार हो और सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए जिसको लेकर जब बीसलपुर एसडीओ प्रवीन कनौजिया से जानकारी ली तब उन्होंने बताया जिन लोगों के प्रीपेड कनेक्शन है उन सभी लोगों के कनेक्शन कटे हैं चार से पांच दिन में बाकी कनेक्शन काट दिए जाएंगे मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति के संग भेदभाव नहीं किया जा रहा है

बीसलपुर में भाजपा नेता रत्नेश गंगवार का अनोखा कदम: सम्राट अशोक जयंती पर ग्राम रोहनिया में रहे ग्रामीणों के बीच

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर, 130 विधानसभा क्षेत्र। भाजपा के प्रमुख नेता रत्नेश गंगवार ने महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम रोहनिया में एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने पूरे दिन ग्रामीणों के बीच रहकर सम्राट अशोक के धम्म, अहिंसा और शांति के महान संदेश को जन-जन तक पहुंचाया। यह आयोजन क्षेत्रवासियों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ।

कार्यक्रम की शुरूआत सम्राट अशोक की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। रत्नेश गंगवार ने ग्रामीण सभा को संबोधित करते हुए कहा, "सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाकर विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाया। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। हम सबको उनके धम्म चक्र को घुमाना चाहिए।" उन्होंने ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन जीने का संदेश दिया।

स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया। कार्यक्रम में भजन-कीर्तन, धम्म प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जिससे क्षेत्र में उनकी सादगी और जनसेवा की भावना की सराहना बढ़ी। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का था, बल्कि सामाजिक एकता को मजबूत करने वाला भी सिद्ध हुआ।